भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-110

उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

नई शिक्षा नीति, 2020

†*110. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:
श्री एम. के. राघवनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और किन-किन राज्यों ने राज्य-वार इस नीति को अपनाया है और लागू किया है;
(ख) नई शिक्षा नीति, 2020 को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(ग) क्या शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता में बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप संबंधी चिंताओं कारण नई शिक्षा नीति, 2020 को अपनाए जाने का विरोध किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केरल सरकार राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने पर सहमत हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या उक्त नीति में इसे लागू न करने का विकल्प चुनने वाले राज्यों के लिए कोई वैकल्पिक प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में हितधारकों की चिंताओं को दूर करने हेतु उनके साथ बातचीत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

नई शिक्षा नीति, 2020 के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. गुम्मा तनुजा रानी और श्री एम. के. राघवन द्वारा पूछे गए दिनांक 08.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 110 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के पश्चात, इसके कार्यान्वयन के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में अनेक परिवर्तनकारी परिवर्तन हुए हैं।

स्कूल शिक्षा में एनईपी 2020 के विजन के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं जैसे कि:-
समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक विस्तारित है। इसका उद्देश्य स्कूल की प्रभावशीलता को बेहतर बनाना है, जिसे स्कूल शिक्षा के लिए समान अवसर और निष्पक्ष अधिगम परिणाम के तौर पर मापा जाता है। इसकी संरचना को 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जो बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक चरण के अनुसार है। यह योजना शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के साथ पूरी तरह से अनुकूलित किया गया है।

पीएम पोषण योजना: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना को नया रूप दिया गया है और सरकारी और सरकारी सहायता वाले स्कूलों में कक्षा I-VIII के विद्यार्थियों के अलावा बालवाटिका के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर, सभी स्कूलों में स्कूल पोषण गार्डन (एसएनजी) बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा समुदाय की भागीदारी को और सुदृढ़ करने के लिए, 'तिथि भोजन' नाम की एक विशेष पहल शुरू की गई है।

बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को शुरु किया गया था। इसके आधार पर, कक्षा I और II के लिए अधिगम शिक्षण सामग्री (जादुई पिटारा) और पाठ्यपुस्तक जारी की गई हैं।

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) दिनांक 23 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। एनसीएफ-एसई के तहत, पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है, जिसमें स्कूल शिक्षा के 5+3+3+4 डिज़ाइन पर बल दिया गया है। इस रूपरेखा में बुनियादी चरण से लेकर माध्यमिक चरण तक की पूरी शिक्षा यात्रा पर ध्यान दिया गया है। एनसीएफ-एसई (2023) के अनुसार कक्षा 3 से 8 के लिए पाठ्यपुस्तक जारी कर दी गई हैं।

मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सार्वभौमिक बनाने के लिए दिनांक 05 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया, जिसे राष्ट्रीय बोध पठन एवं संख्याज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत) कहा जाता है।

विद्या प्रवेश (वीपी), एक 3 माह का प्ले बेस्ड स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया और दिनांक 29 जुलाई, 2021 को शुरु किया गया था। यह मॉड्यूल 12 सप्ताह का है और इसमें कक्षा-I में आने वाले बच्चों के विकास के अनुसार उपयुक्त निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चे की पूर्व-साक्षरता, पूर्व-संख्याज्ञान, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों को बेहतर बनाया जा सके। विद्या प्रवेश अब एक वार्षिक कैलेंडर है और कक्षा I के 4.2 करोड़ से अधिक बच्चों को वीपी से लाभ हुआ है।

एनसीटीई द्वारा दिनांक 22.10.2021 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए मानदंड और मानक अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक, 64 संस्थानों को 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए मान्यता दी गई, जिसमें 6,100 छात्र शामिल हुए।

विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) की शुरुआत दिनांक 6 सितंबर, 2020 को हुई।

स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) दिनांक 21 अगस्त 2019 को शुरू की गई और ईसीसीई के लिए मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण सहित स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों को कवर करने के लिए विस्तारित की गई।

विद्यार्थियों के मूल्यांकन से संबंधित मानदंडों, मानकों, दिशानिर्देशों को स्थापित करने और गतिविधियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना दिनांक 8 फरवरी, 2023 को की गई थी।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों (केंद्र और राज्य सरकार), सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों सहित स्कूलों के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया था। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों के नमूने का मूल्यांकन करके स्कूल शिक्षा के बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों का आकलन करना था।

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) शिक्षकों के कार्य को परिभाषित करता है और 21वीं सदी के स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले, प्रभावी शिक्षण के तत्वों को स्पष्ट करते है जिससे छात्रों के लिए शैक्षिक परिणाम बेहतर होंगे। एनसीटीई ने एक मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार किया है जो उन दक्षताओं को दर्शाता है जो शिक्षकों में अपनी भूमिकाएं प्रभावशाली तरीके से

निभाने के लिए होनी चाहिए। एनपीएसटी मार्गदर्शक दस्तावेज दिनांक 9 मार्च, 2024 को जारी किया गया और अब यह 22 भारतीय अनुसूचित भाषाओं और ब्रेल संस्करण और ऑडियो प्रारूप में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन (एनएमएम) का उद्देश्य स्कूल शिक्षकों को परामर्श प्रदान करने के इच्छुक उत्कृष्ट पेशेवरों का एक बड़ा समूह तैयार करना है। 'एनएमएम संबंधी ब्लूबुक' दिनांक 9 मार्च, 2024 को जारी की गई थी और अब यह 22 भारतीय अनुसूचित भाषाओं और ब्रेल संस्करण और ऑडियो प्रारूप में उपलब्ध है।

पीएम ई-विद्या के अंतर्गत, दीक्षा एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा अवसंरचना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में शामिल किया गया है। यह डिजिटल अवसंरचना कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है और अत्यधिक व्यापक है। इस अवसरंचना का उपयोग सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) को तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है और वर्तमान में दीक्षा पर 7,497 ईटीबी प्रकाशित हैं। दीक्षा और ई-विषयवस्तु पर 135 भाषाओं (128 भारतीय + 7 विदेशी भाषाओं) में कुल 3,74,460 ई-सामग्री उपलब्ध है।

स्वयम् प्रभा के डीटीएच चैनलों का विस्तार 200 चैनलों तक किया गया है और यह स्कूल शिक्षा के लिए हैं, जिसका उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। यह 30 भाषाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य क्षेत्रों से प्राप्त कुल 92,147 वीडियो विषय-वस्तु के साथ 30585 घंटे के प्रसारण के समान है।

पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना दिनांक 7 सितंबर, 2022 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 14500 से अधिक चयनित स्कूलों को उदाहरणपरक स्कूलों के रूप में तैयार करना है, जो एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं।

उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम की समझ), प्रौढ़ शिक्षा पर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित है और इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के कम पढ़े-लिखे लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। शिक्षार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों को रजिस्टर करने और 26 भाषाओं में प्राइमर्स तक पहुंच सुलभ बनाकर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिनांक 29.07.2023 को एक समर्पित मोबाइल ऐप शुरु किया गया था। 3.09 करोड़ से ज़्यादा शिक्षार्थियों और 46.52 लाख स्वैच्छिक शिक्षकों (वीटी) रजिस्टर हो चुके हैं। अब तक, 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात लद्दाख, गोवा, मिज़ोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से साक्षर घोषित किया जा चुका है।

शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए आगामी पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। एनईपी 2020 के विजन के तहत उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अनेक परिवर्तनकारी सुधार और पहल भी शुरू की गई हैं।

शैक्षणिक रूपरेखा और मानकीकरण के क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ) और इसकी मानक संचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ताकि शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षणिक, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा का निर्बाध एकीकरण संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ) का उद्देश्य समकक्षता और तुलनीयता के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में योग्यता स्तरों का मानकीकरण करना है।

स्वचालित स्थायी शैक्षणिक लेखा रजिस्ट्री (अपार आईडी) की शुरूआत से विद्यार्थियों को प्री-प्राइमरी से उच्चतर शिक्षा तक अपने अधिगम की यात्रा को ट्रैक करने के लिए आजीवन शैक्षणिक पहचान प्राप्त होती है। एबीसी पोर्टल पर 2600 से अधिक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को शामिल किया गया है और 4.50 करोड़ से अधिक छात्र पहले से ही पंजीकृत हैं।

सुलभता और किफायतता में सुधार के लिए, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, जो सरल, पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से योग्य छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

इसके अतिरिक्त, नियमित कार्यक्रमों के साथ गुणवत्ता और समता सुनिश्चित करने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) और ऑनलाइन शिक्षा के लिए नियामक रूपरेखा को संशोधित किया गया है। वर्तमान में, 126 उच्चतर शिक्षा संस्थान लगभग 802 ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और 121 उच्चतर शिक्षा संस्थान लगभग 1699 ओडीएल कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, आगामी तीन वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में विभिन्न स्कूल और उच्चतर शिक्षा विषयों में पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी विद्यार्थियों को परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं में उत्तर लिखने की अनुमति देता है, भले ही कार्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में प्रस्तुत किया जा रहा हो और स्थानीय भाषाओं में मूल लेखन के अनुवाद को बढ़ावा देता है और विश्वविद्यालयों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देता है। 10 राज्यों में 41 संस्थान 12 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। 13 भाषाओं में आयोजित सीयूईटी में

लगभग 240 संस्थानों ने भाग लिया। जेईई (मुख्य) और नीट (यूजी) 13 भाषाओं में आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 30 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए।

स्वयम प्लेटफ़ॉर्म के एकीकरण के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को सुदृढ़ किया गया है, जिससे अब कुल प्रोग्राम क्रेडिट का 40% तक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। कुल 404 विश्वविद्यालयों ने स्वयम को अपनाया है, जिसमें प्रति वर्ष 5 करोड़ से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख प्रमाणपत्र प्रदान करना शामिल हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, स्वयं प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो कार्यबल के कौशल विकास और पुनर्कौशल पर केंद्रित है। आज की स्थिति के अनुसार 4.65 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है।

अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अनुसंधान क्षमता का उपयोग करना, शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और उभरती प्रौद्योगिकियों एवं राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रूपांतरणात्मक अनुसंधान को सुगम बनाना है। एएनआरएफ का लक्ष्य वर्ष 2023-28 के दौरान ₹50,000 करोड़ जुटाना है, जिसमें केंद्र सरकार से 14,000 करोड़ रुपए और शेष राशि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से एएनआरएफ निधि, नवाचार निधि और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान निधि जैसे विभिन्न निधियों के माध्यम से जुटाई जाएगी।

इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में शोध की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) कार्यान्वित किया जा रहा है। आकर्षक अध्येतावृत्ति के साथ, इसका उद्देश्य शोध के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना है ताकि नवाचार के माध्यम से विकास के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

"भारत में एआई बनाएं और भारत के लिए एआई को काम में लाएं" के विजन को साकार करने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि में 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को अनुमोदित किया था। शिक्षा मंत्रालय ने तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) - आईआईएससी बेंगलुरु में स्वास्थ्य में एआई का सीओई, आईआईटी रोपड़ में कृषि में एआई का सीओई और आईआईटी कानपुर में दीर्घकालिक शहरों में एआई का सीओई की स्थापना के लिए तीन शैक्षणिक संस्थानों को अनुमोदित किया था। इसके अतिरिक्त, बजट 2025-26 में 500.0 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के लिए शिक्षा में एक नए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की घोषणा की गई है।

शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देते हुए, सरकार ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं (एफएचईआई) की स्थापना को संभव किया है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के एफएचईआई को भारत में बेंगलुरु (कर्नाटक), दिल्ली एनसीआर, मुंबई (महाराष्ट्र) और चेन्नई (तमिलनाडु) सहित विभिन्न स्थानों पर अपने परिसर स्थापित करने के लिए 13 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से यूके की साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के गुरुग्राम के अपने परिसर में अगस्त, 2025 में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) विनियम 2022 के तहत, यूके, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी आयरलैंड के 5 विश्वविद्यालयों को गिफ्ट सिटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात में अपतटीय शाखा परिसरों के संचालन के लिए अनुमोदन दिया गया है। इन 5 विश्वविद्यालयों में से, ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने जुलाई, 2024 में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए और ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने नवंबर, 2024 में अपने पाठ्यक्रम शुरू किए। इसके अलावा, भारतीय संस्थान अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली और तंजानिया में आईआईटी मद्रास के परिसर के साथ वैश्विक उपस्थिति भी स्थापित कर रहे हैं। ये कदम भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य में सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त, विनियामक प्रावधान अब भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के बीच अकादमिक सहयोग के माध्यम से युगल, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की अनुमति देते हैं, वर्तमान में 230 पात्र विश्वविद्यालयों में से 103 संस्थान ऐसे कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्यूएस रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान शामिल हैं, जबकि वर्ष 2015 में यह संख्या 11 थी। क्यूएस विषयवार रैंकिंग 2025 में 79 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान शामिल थे, विगत वर्ष के 69 से 10 की वृद्धि हुई, जिससे उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की संख्या में 14% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 के अनुसार, 294 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान शामिल हैं।

उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना शुरू की गई है, जिससे 526 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में 18,216 विषय विशेषज्ञों की सहभागिता संभव हो सकेगी।

भारतीय मूल्यों, विरासत और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षा पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान परंपरा (आईकेएस) के व्यवस्थित एकीकरण के साथ सांस्कृतिक और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सुदृढ़ करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और शोध-आधारित पारंपरिक भारतीय ज्ञान परंपरा और समकालीन ज्ञान प्रणालियों के बीच के अंतर को कम करने के लिए आईकेएस योजना को 405.78 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर वर्ष 2029-30 कर दिया गया है।

(ख) से (ङ): शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा क्षेत्र में समग्र गुणवत्ता और विकास के व्यापक और प्रगतिशील संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। एनईपी 2020 का उद्देश्य शिक्षा पर विधि तैयार करने के लिए राज्य की शक्तियों से वंचित करना नहीं है बल्कि इस नीति के निष्पादन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना, संयुक्त निगरानी और सहकार्यात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

एनईपी के कार्यान्वयन हेतु जागरूकता पैदा करने और नवाचारी विचारों के संबंध में चर्चा करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला समय-समय पर आयोजित की गई है। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर जून 2022 में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन; जून 2022 में आयोजित मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन; अगस्त 2022 में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक; अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022, 2023, 2024 और 2025; दिनांक 27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक; दिनांक 12 और 13 नवंबर 2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के साथ उच्चतर और तकनीकी शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला; केंद्रीय विश्वविद्यालयों की शैक्षिक परिवर्तन के प्रेरक के रूप में भूमिका और विकासित भारत @2047 में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया, प्रगति की समीक्षा और भविष्य की रूपरेखा स्थापित करने हेतु दिनांक 10 और 11 जुलाई 2025 को केवड़िया, गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन; एनईपी के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी विनियमों, बहु-विषयक शिक्षा के लिए क्लस्टरिंग और सहकार्य, कौशल और उद्योग कनेक्ट के एकीकरण के माध्यम से समग्र शिक्षा आदि विषयों पर चर्चा हेतु 30 अप्रैल से 1 मई, 2025 तक प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के अंतर्गत बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा की गई।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन समतुल्यता और अधिगम परिणामों में सुधार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 02.07.2025 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 250 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य आकर्षणों में परख प्रसार पोर्टल का शुभारंभ, राज्य-स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुतियां, बोर्ड समकक्षता के लिए रूपरेखा पर विचार-विमर्श और एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप अधिगम परिणामों को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां शामिल थीं।

एनईपी 2020 में इसके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समय-सीमाओं के साथ-साथ सिद्धांतों और पद्धति का प्रावधान है। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक

अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल करना शुरू कर दिया है।

*****